

पत्र-23

परियोजना का नाम :- गुनियाघोली-विशालकोट मार्ग का ग्राम टाका हर  
कोटिया-देवी विशालकोट मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तसवास  
 तहसील राजीवपुर, जिला कैमोज

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कैमोज के अन्तर्गत गुनियाघोली-विशालकोट मार्ग का विस्तार  
 के निर्माण हेतु ( 0.450 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.450 हे० सिविल सोयम भूमि 0.450 हे०,  
 वन पंचायत भूमि 0.450 हे०) अर्थात् कुल 0.900 हे० वन भूमि का  
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
 द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तसवास द्वारा दिनांक 10/01/16 को  
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
 अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
 कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
 आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
 किया गया कि ग्राम तसवास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
 कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- [Signature]  
 ग्राम सचिव

अनापत्ति देवी

ग्राम पंचायत तसवास  
 ह०/- [Signature]  
 ग्राम प्रधान

Parsevan

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
 एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 01/01/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .....  
तस्वाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित दूरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
2-	कै-पनरिह	कै-पनरिह
3-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
4-	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
5-	बनारस प्रसाद (बालाजी)	बनारस प्रसाद
6-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
7-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
8-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
9-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
10-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
11-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
12-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
13-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
14-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
15-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
16-	बनारस प्रसाद	बनारस प्रसाद
17-		
18-		
19-		
20-		

बनारस प्रसाद

ग्राम पंचायत तस्वाड  
पिन कोड 190001  
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम

प्रपत्र-23/2

गजियादौली विशालकोट मार्ग का ग्राम राजा तस्वाड कोठिया - डौली विशालकोट मार्ग का नवनिर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

तस्वाड कोठिया डौली उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत गजियादौली-विशालकोट मार्ग का ग्राम राजा तस्वाड कोठिया डौली मोरमारा हे० आरक्षित वन भूमि ०.५५० हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.५५० हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.५०० हे० वन भूमि ) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रानीखेत) की दिनांक 12/01/2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनीत कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |  |
|----|--|
| 1- | श्री <u>विनीत कुमार</u> उपजिलाधिकारी <u>रानीखेत</u> अध्यक्ष                    |
| 2- | श्री <u>पी. के. सिंह</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>रानीखेत</u> सदस्य            |
| 3- | श्री <u>पी. सी. पन्त</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>रानीखेत</u> सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>अम्बिका दत्त पन्त</u> बी०डी०सी० क्षेत्र <u>रानीखेत</u> सदस्य           |

कनिष्ठ उप-प्रमुख

हास खण्ड-ताडीखेत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गजियादौली-विशालकोट मार्ग का ग्राम राजा तस्वाड कोठिया - डौली विशालकोट मोरमारा

परियोजना हेतु ०.५०० हे० वन भूमि ५०० वर्ग मी० विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2006 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
हेठ वन भूमि 100 फीट प्रयोक्ता एजेंसी का जनहित में परियोजना के निर्माण हेतु 02/07/00  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— रानीखेत  
जनपद— जल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— रानीखेत  
जनपद— जल्मोड़ा



प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- गोनियाडोली - विशालकोट मार्ग का ग्लाम लाना  
कस्बाड - कोहिमा डोली विशालकोट मार्ग का नवनिर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त

परियोजना के निर्माण हेतु 0.900 हे० वन भूमि जैव विविधता (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
धरमपुरा

  
जिलाधिकारी

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.900 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

  
Signature  
जिला अधिकारी  
(Full name of the official seal of the District Collector)  
अल्मोड़ा

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Almora**

No : .....

Dated: 15-01-2016

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.900 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. P.D. PWD, Ranikhet Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Extension of Ganiidhadi Vishalkote Motor road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Taraswar village(s) in Ranikhet Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.900 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

D.M.

Signature  
जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा


(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Savin Bansal**, I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....15-01-2016.....at time.....3:20 PM.....at Almora. in which application claiming rights of ..... area measuring 0.900 hect. for the Construction of Ganiadhyali Vishalkote motor road via Tana, Taxasuri, Dharito Vishakot of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date : 15-01-2016

  
Signature  
(Full name of the official seal of the District Collector)  
**जिला अधिकारी**  
**अरमोदा**